Need to clear pending Thermal Power Projects in Maharashtra

डा० बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : महोदया, महाराष्ट्र में कुछ विकास की प्रक्रिया में अति आवश्यक बिजली के सम्बन्ध में आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। आप जानती हैं कि महाराष्ट्र एक अति प्रगतिशील राज्य है और महाराष्ट्र की यह इच्छा है कि खेती के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रयास करे। इस संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास यूजनी स्टेज-1, भुसावल, धाबोर, बरनी स्टेज-ब्री और उमेर ऐसे पांच थरमल पावर स्टशनों की मांग कई वर्षों से की हुई हैं। यूजनी 1975 की है, भुसावल 80 की है, धाबोर 81 की है और बरनी एवं उमेर 86-87 की हैं। अगर इनके नाम आप देखें, क्यों कि आप महाराष्ट्र को जानती हैं, इन सारे थरमल पावर स्टशनों की मांग जो है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की है और इस में भी मराठवाड़ा, कोंकण और विदर्भ रीजन की हैं जो महाराष्ट्र में सबसे पिछड़े इलाके माने जाते हैं। इस मांग को आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोल लिंकेज के कारण मान्यता नहीं मिली ऐसा हमें कहा गया है। हम आप से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को क्लीअर किया जाये। होता यह कि जमीन लेना और उसका सारा इन्फास्ट्रक्चर तैयार करना आदि में 5—6 साल की अवधि लगती हैं। अगर आज यह क्लीयर कर दें तो कोल लिंकेज की बात नाइन्थ प्लान में पूरी कर सकते हैं उसके बाद भी उसके काम में जो बिजली के केन्द्र होंगे वे सारे प्रोजेक्ट्स काम में आ सकते हैं। इसके लिए मेरा आप के द्वारा ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि जो पांच थरमल पावर स्टेशन की मांग महाराष्ट्र सरकार ने कई वर्षों से की है उस वह पूरा करे और इन प्रोजेक्ट्स का जो संस्थान बनाना चाहते हैं उनकी वह अनुमति दे दें ताकि उसकी अन्तिम प्रक्रिया नाइन्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू हो जाए और नाइंथ पंचवर्षीय योजना के अंत तक जो बिजली की मांग महाराष्ट्र में बढ़ती रहेगी वह मांग पूरी करने की क्षमता महाराष्ट्र में आ जायेगी। इसी के साथ आप से दर्खास्त है कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस मांग को पूरा करने के लिए जो कुछ भी प्रयास करना है उसमें आप भी हमारी मदद करें। धन्यवाद।

Demonstration by displaced Tribals and Adivasis against Narmada Sagar and Sardar Sarovar Projects

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उपसभापति महोदया, मैं एक बहुत ही गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यह मामला हमारे दो प्रांतों गुजरात और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। पिछले कई वर्षों से यह मामला लम्बित है। नर्मदा के ऊपर नर्मदा सागर योजना और सरदार सागर योजना बननी है। इसमें कुछ बातें होनी चाहिए थीं, जैसे पर्यावरण विभाग से अनुमति लेकर पर्यावरण खराब न हो उसके हिसाब से काम होना चाहिए था। जो लोग उजड़ जाएंगे उनके बारे में क्या होगा, उस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए था। और भी बहुत सी बातें है जो नहीं हो सकी। कल प्रधान मंत्री भवन के समक्ष बाबा आम्टे, श्री सुन्दरलाल बहुगुणा और श्री मेदा पटवर के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों और कृषकों ने जो नर्मदा वैली में बसते हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन का मुद्दा था कि नर्मदा सागर योजना और सरदार सागर योजनाओं का दुबारा रिएसेसमेंट किया जाय और इस विषय को फिर से देखा जाय कि यह उचित होगा या नहीं। मैं आपके सामने यह बात लाना चाहूंगी कि इस योजना को लागू होने में 54106 हेक्टियर जंगल डूब जाएगा, 55681 हेक्टियर खेती योग्य जमीन डूब जाएगी और 502 गांव उजड़ जाएंगे जिसमें 2 लाख 30 हजार आबादी आदिवासियों और पिछड़े वर्गों की है और अन्य कृषकों की हैं। इनकी जमीन बर्बाद हो जाएगी डूब जाएगी। ये दोनों योजनायें कंडीशनल थीं इनवाइरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से और प्लानिंग मिनिस्ट्री की तरफ से। दूसरा उनके पुनर्वास का भी सवाल

था जिन बातों की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए था। इसके अलावा यह भी सवाल है कि हमारे देश में जंगल नियमानुसार 33 प्रतिशत होने चाहिए, लेकिन हिन्दुस्तान में केवल 11 प्रतिशत सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हैं। लेकिन सचमुच में सरकारी विभाग और पर्यावरण विभाग यही कहते हैं कि केवल मात्र जंगलों का आवरण 7 प्रतिशत है। यह स्थिति पूरे देश के पर्यावरण को और सारे इको सिस्टम को चेन्ज कर देगा। आप देख रही हैं कि बारिस का चरित्र बदल रहा है, फसलें समय पर नहीं हो रही हैं और दूसरे इकोलोजिकल चेन्जज भी हो रहे हैं। इस नर्मदा सागर योजना से बाद में फ्लोरा और फौना में भी चेन्ज होगा। इको इम्बेलेन्स और वाटर लोगिंग होगा और कमान्ड एरिया में जो सेलीनेशन की जांच होनी चाहिए थी वह भी नहीं की गई। जब यह प्लान आया था तो 1980 में इसकी कास्ट 6406 करोड़ थी और अब यह 11,165 करोड़ की हो गई है और आगे और भी बढ़ेगी। महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि सरकार इन सभी बातों पर ध्यान देकर नर्मदा सागर और सरदार सागर परियोजनाओं पर पुर्नविचार करें और विस्थापितों को फिर से बसाने और फोरेस्टेशन की समस्याओं के बारे में गम्भीर रूप से विचार करे।

1 P. M.

Criticism of R.A.W. by Tamil Nadu Chief Minister

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri V. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam Deputy Chairman, I thank you for giving me this opportunity to raise an issue of great importance about the RAW which is an international intelligence organisation working for the country and they have been doing a very good job and furnishing information to the Government of India for the unity and integrity of this nation. Madam, it is quite unfortunate that the political personalities and the leader of a particular political party in Tamil Nadu criticised the activities of RAW and termed them as giving false information to the Government of India about the LTTE militants. They have been telling that LTTE militants have been ruling the southern coastal Tamil Nadu and that particular political party which is ruling Tamil Nadu is supporting the activists. Madam, it is a matter of great shame on the part of our Indian Government that the political leader is trying to tarnish the image of the intelligence organisation of this country and the same is condemnable. Madam, I was happy when the matter was confronted with the Prime Minister. He said in categorical terms that it is unjusitfied, that the Chief Minister Shri Karunanidhi's criticism of RAW was not proper... *(Interruptions)*... To make charges in public about an intelligence agency is unjustified. ...*(Interruptions)*... The criticism is unjustified. Madam, it is not only about that agency, but they went to the extent of even accusing the IPKF, connecting it with RAW. They said that IPKF was committing genocide in Sri Lanka. Madam, with great pain I would like to say that a true nationalist who has respect for this country, who supports the unity and integrity of this country will not say that IPKF is committing genocide. ...*(Interruptions)*...

SHRI T. R. BALU (Tamil Nadu): Madam, this is not proper. ...*(Interruptions)*... This is not correct. ... *(Interruptions)*....

SHRI V. NARAYANASAMY: I am telling about the character ...*(Interruptions)*... I am telling about the character of persons who are holding high office. ..*(Interruptions)*...

AN HON. MEMBER: Madam, it is to criticise a political party and it is not within the parameters...*(Interruptions)*...